

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्यो. सं. 1/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दवा बाबत खाला तकसीम अन्तर्गत धारा 88 एवं 53 राजस्थान कारतकारी अधिनियम इन तथ्यों के साथ प्रस्तुत किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 सगे माई बहन है एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 वादी के पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 तथा उनके पिता स्व. पाखर सिंह एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य थे और उनके पास पूर्वजों से प्राप्त वैदिक सम्पत्ति थी। उसकी आय से एवं वादी एवं परिवार के अन्य सदस्यों के सहयोग से जो आय प्राप्त हुई उससे एवं पंजाब में जो फरिफेन की संयुक्त सम्पत्ति थी उसकी बिक्री से प्राप्त राशी से वादी के पिता स्वर्गीय श्री पाखर सिंह ने 23 बीघा कृषि भूमि दिनांक 01.02.63 को जारिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की, परन्तु बैयानकर्ताओं के खाले में 21 बीघा भूमि थी जिसका इत्नाकाल मुताबिक बैयनामा

दिनांक:- 9.9.21

निर्णय  
 श्री रविन्द्र कुमार मीठिया राजकीय अधिवक्ता रेस्यो सं 6  
 श्री इन्दरज गोदरा अधिवक्ता रेस्यो 3, 4, 5 ।  
 श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलार्थ

वर्षिष्ठ:-

28.05.2014



अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2002 व डिक्री दिनांक 22.03.2002 न्यायालय सहायक कलक्टर संगरिया कैम्प टिब्बा वाद संख्या 179/87 उनवानी गुरनाम सिंह बनाम गुरबचनसिंह आदि एवं संशोधित निर्णय एवं डिक्री दिनांक

- रेस्यो/डिप्टस

6. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार टिब्बा जिला हनुमानगढ़।
5. दलीप सिंह
4. बलजीत सिंह } तहसील टिब्बा जिला हनुमानगढ़।
3. मोठा सिंह } पिसरान गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जालि कुम्हार सिख निवासी मसानी
2. स० छोटी पुत्री पुत्री पाखर सिंह जालि कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बा जिला हनुमानगढ़।  
 तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
- 1/1. गृहणी उर्फ नसीबकौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी सुखदेवसिंह जालि कुम्हार सिख वीपीओ ठांवा (कौत)
1. गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जालि कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बा जिला हनुमानगढ़।

बनाम

-अपीलार्थ

1. गुरबचन सिंह } पिसरान पाखर सिंह जालि कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील टिब्बा
  2. हरजीत सिंह } जिला हनुमानगढ़।
  3. जगजीत सिंह
- अपील संख्या 2014/00381 (143/2014) 223 आरटीएक्ट



**पीठासीन अधिकारी :- करतार सिंह पुनियाँ आर.ए.एस.**  
**न्यायालय राजस्थान अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़**

अधीनस्थ  
राज्य अधीनस्थ प्राधिकारी

कै दर्ज हुआ। उक्त वर्णित 21 बीघा आराजी वादी के पिता ने संयुक्त परिवार के कोष से खरीद की थी। उस समय वादी उपस्थित नहीं था इसलिए बैयनामा में वादी का नाम सहबन से दर्ज नहीं करवाया गया, किन्तु वास्तव में उक्त मूंसि संयुक्त परिवार की सम्पत्ति है एवं वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बराबर के हकदार है। स्वर्गीय पाखर सिंह ने अपनी जिन्दगी में उक्त वर्णित आराजी में से 5 बीघा मूंसि की वसीयत प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के हक में निष्पादित कर दी। प्रतिवादीगण ने उक्त संयुक्त सम्पत्ति में वादी के हिस्से को कभी इन्कार नहीं किया और वादी के हिस्से का मुकाद उसे देते रहे इसलिए पहले कोई विवाद नहीं होने के कारण वादी ने रिकॉर्ड में दुरस्ती नहीं करवाई। उक्त संयुक्त कृषि मूंसि में प्रतिवादी सं. 5 ता 7 के हक में निष्पादित वसीयत की 5 बीघा मूंसि को काटने के पश्चात बाकी बची 16 बीघा मूंसि में से पाखर सिंह के वैध वारीसान की हैसियत से वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 4 बहिस्सा बराबर के हकदार है। पाखर सिंह के देहान्त के पश्चात आराजी का इन्तकाल मालत रूप से दर्ज हुआ है एवं वादी के नाम केवल कुछ बिस्वा का ही इन्तकाल हुआ है, जिसका वादी के हक हकक पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः वादी ने एक नम्बर 13 जी.जी.आर के कुल 5.313 हेक्टर आराजी में से वादी को 3 बीघा 4 बिस्वा कृषि मूंसि का खातेदार काइलकार घोषित किये जाने एवं अलग अलग किये जाकर कब्जा दिलाने तथा वादी के हिस्से का अलग से रकम राज निर्धारित किये जाने का अनुरोध याहा। प्रतिवादी सं. 5 ता 7 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर उन्हें प्राप्त 5 बीघा मूंसि का अलग से खाला कायम किये जाने एवं विकल्प में अर्जादावा में वर्णित विवादित मूंसि में से अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी 5 बीघा मूंसि का खाला तकसीम कर अलग से खाला कायम किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी 1 ता 3 द्वारा जवाबदावा पेश किया गया कि 1953 में ही वादी में ही वादी अपने पिता एवं माईया से ही अलग हो गया था। पूर्वक सम्पत्ति की जो जमीन थी उसके हिस्से के जो रूपय बनते थे उसके रूपय वादी ने पहले ही ले लिए थे। आराजी मुतनाजा प्रतिवादी सं. 1 ता 3 ने 10 बीघा खरीदी एवं 13 बीघा मूंसि प्रतिवादी 1 ता 3 के पिता एवं प्रतिवादी 1 ता 3 ने अपनी कमाई से पिता के नाम से खरीद की। लेकिन कब्जा 21 बीघा मूंसि का ही देलवाया गया था। वादी का आराजी मुतनाजा में कोई हिस्सा नहीं है। वादी एवं उसके लड़के दुरभिसंधि किये हुए है तथा हम प्रतिवादीगण से जमीन हड़पने के लिए यह दावा पेश किया है जिसे खारिज फरमाया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादी एवं जवाबदावा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 स्वीकार कर एक 13 जी.जी.आर जमाबन्दी सम्वत् 2042 खाला सं. 32/6 खाला गुरवरण सिंह आदि में दर्ज 2 बीघा 5 बिस्वा मूंसि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 ता 7 को अपने हिस्से अनुरार अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी का आदेश प्रासिक हिस्से जायी कर तहसीलदार टिब्बी के विमानन प्रस्ताव के अनुरार निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं हिस्से जायी किये गये, एवं दिनांक 28.05.2014 को संशोधित आदेश जायी कर निर्णय एवं हिस्से में संशोधन किया गया। जिससे व्यहित होकर अधीनस्थ ने यह

अपील प्रस्तुत की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अधीनस्थ ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रासिक

आदेश एवं हिस्से के विरुद्ध न्यायालय राजस्व अधीनस्थ प्राधिकारी, हनुमानगढ़ में अपील दायर की गई थी जिसमें दिनांक 19.10.2001 को निर्णय पारित किया जाकर अपील अधीनस्थ खारिज होने पर हितीय अपील माननीय राजस्व मंडल अजमेर में दायर की गई जो दिनांक 09.01.2014 को खारिज होने के बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचारणीय है। ऐसी स्थिति में जब प्रासिक हिस्से चुनौती अधीन है तो विचारण न्यायालय द्वारा अन्तिम हिस्से जायी नहीं की जा सकती। इस कारण अधीनस्थ निर्णय एवं हिस्से खारिज किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 13.03.2001 को प्रासिक हिस्से जायी की



गई एवं विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार हल्का टिब्बी से आमंत्रित किये गये परन्तु विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व हल्का तहसीलदार द्वारा अधीनकार को किस्सी किस्म का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया एवं ना ही मौका पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार किया बल्कि तहसील मुख्यालय पर ही रेस्सी. सं. 1 व 5 ता 7 के कहे अनुसार प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय को भिजवाया जाना प्रतीत होता है। हल्का तहसीलदार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना किये बिना यथासंभव जहां कच्चा हो उसी अनुसार विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने के प्रावधानों से परे जाकर कतई मननजी से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष भिजवाया गया एवं विचारण न्यायालय द्वारा भी नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित ना कर मनमाना आदेश पारित करने की गलती की है, जो निरस्ती योग्य है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राप्त विभाजन प्रस्ताव में गुरनामसिंह पुत्र पोखरसिंह 0. 303 हिस्सा अंकित किया गया था जबकि अधीनस्थान निर्णय में उक्त हिस्सा बिना किस्सी विवेचन किये 0. 304 हिस्सा अंकित कर दिया गया एवं गुरनामसिंह, मोठसिंह, बलजीत सिंह, दलीपसिंह को विभाजन प्रस्ताव में एक 13 जी.जी.आर. पं० नं० 188/276 मु० नं० 23 किला नं० 25/0.253 है 0 नहरी मु० रास्ता, पं० नं० 190/277 मु० नं० 36 किला नं० 4, 5, 7/0.759 अ० क० मय मु० रास्ता पं० नं० 188/277 मु० नं० 38 4, 5/0.506, 7/0.51 नहरी मय मु० रास्ता कुल 1.569 है 0 मुगाधिक विभाजन प्रस्ताव दी गई है। उक्त भूमि में से पं० नं० 188/277 किला नं० 4, 5 पर मौके पर जगजीतसिंह रेस्पो सं० 7 काबिल है एवं पं० नं० 188/277 किला नं० 7 की 0.51 पर गुरबचन सिंह अधीनकार सं० 1 काबिल है तथा पं० नं० 190/277 किला नं० 7/0.253 है 0 पर हरजीत सिंह अधीनकार सं० 2 का कच्चा है। परन्तु उक्त स्थिति को देख बिना एवं रास्ता खाला वगैरा का ध्यान किये बिना प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अधीनस्थान निर्णय एवं हिस्सी पारित करने में सख्त गलती की है। जिससे की अधीनस्थान निर्णय एवं हिस्सी काबिल निरस्ती है। इसके अतिरिक्त 12 वर्ष बाद हिस्सी में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह अधीन अन्तिम हिस्सी के विरुद्ध है जिसके विरुद्ध पूर्व में कोई अधीन प्रस्तुत नहीं हुई है। अधीनकार अधीनकार नो अपनी बहस में कथन किया कि अधीनकार एवं रेस्पोडेण्टस सं 3 ता 5 के पिला रेस्पोडेण्ट सं० 1 व रेस्पो सं० 2 एक ही परिवार के सदस्य है। इनके पिला स्व. पाखर सिंह द्वारा बाद में वर्णित 21 बीघा भूमि रामचन्द्र व धर्मचन्द्र पिसरान मेघाराम से 01.02.63 को जारिये रजिस्टर्ड बैचनमा खरीद की। उक्त 21 बीघा भूमि स्व. पाखर सिंह ने संयुक्त परिवार के कोष से खरीद की थी। लेकिन बैचनमे से वादी का नाम सहचन से दर्ज नहीं करवाया गया। पाखर सिंह ने अपनी खरीददारा भूमि में से 5 बीघा भूमि की प्रतिवादी 5 ता 7 के हक में वसीयत निष्पादित कर दी, जिसका इन्तकाल हमारे नाम से हो चुका है एवं हम रिकॉर्डेड खतदार है। लेकिन 1984 हाईको के परवात प्रतिवादी सं. 2 व 4 ने 2 बीघा भूमि पर जबरदस्ती कच्चा कर लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपन पूर्व निर्णय दिनांक 13.03. 2001 के द्वारा वादी का बाद तथा प्रतिवादी सं. 5 ता 7 का काउटर क्लेम स्वीकार किया। उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्व अधीन प्राधिकारी के समक्ष अधीन सं. 58/2001 प्रस्तुत हुई जिसे राजस्व अधीन प्राधिकारी ने 19.10.2001 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। इसके परवात राजस्व अधीन प्राधिकारी के खिलाफ 09.01.2014 को खारिज हुई उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचारणीय है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई स्थान आदेश नहीं दिया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में



हनुमानगढ़  
राजस्थान  
राजस्थान अपील प्राधिकारी  
अपील प्राधिकारी  
(करतार सिंह पौनधा आरएएस)  
19/12/21

10. निर्णय आज दिनांक 9.9.21 को भेरे द्वारा लिखाया जाकर भेरे इजलास सेनाया गया।

दफतर हो।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विवेचन के अधार पर अपील अपीलाट स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिफ्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिफ्री दिनांक 28.05.2014 खारिज किये जाते हैं। पत्रा डिफ्री जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल

जाने योग्य है।

03.2002 एवं डिफ्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिफ्री दिनांक 28.05.2014 खारिज किये के आलाक में अपील अपीलाट स्वीकार की जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिफ्री दिनांक 22.03.2002 एवं संशोधित निर्णय एवं डिफ्री दिनांक 28.05.2014 को संशोधन किया गया है जो उचित नहीं है। अपीलाट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत RRT 2021 पृष्ठ सं 615 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिफ्री पारित की गई हो एवं उसके विकल्प अपील विचारणीय हो तो अंतिम डिफ्री पारित नहीं की करनी चाहिए। उक्त न्यायिक दृष्टांत के आलाक में अपील अपीलाट स्वीकार की जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिफ्री दिनांक 22.03.2002 को पारित की गई है। जिसमें 12 वर्ष बाद दिनांक 28.05.2014 को संशोधन किया अंतिम डिफ्री पारित किया जाना उचित नहीं है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ निर्णय 21.03.2002 एवं डिफ्री स्थिति में जब प्रारम्भिक डिफ्री माननीय उच्च न्यायालय में चुनौतीधीन है तो विचारण न्यायालय द्वारा जो दिनांक 09.01.2014 को खारिज हुई उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय में रिट विचारणीय है। ऐसी इसके पश्चात राजस्थान अपील प्राधिकारी के निर्णय के खिलाफ माननीय राजस्थान मंडल में अपील प्रस्तुत हुई राजस्थान अपील प्राधिकारी ने 19.10.2001 को खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा। गया। उक्त निर्णय के खिलाफ राजस्थान अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील सं. 58/2001 प्रस्तुत हुई जिसे विभाजन का बाद तथा प्रतिवादी सं 5 ता 7 का काउंटर क्लेम दिनांक 13.03.2001 को स्वीकार किया जाहां तक गुणावर्गण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय में रस्यो सं 1/वादी का धोषा एवं खाला है।



7. अपीलाट द्वारा प्रस्तुत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रार्थना पत्र संशोधन होने एवं उसके साथ प्रस्तुत अपील अपीलाट अन्दर शिमाद शुमार की जाती है।

8. गुणावर्गण पर श्रेयस्कर होने के कारण अपीलाट का धारा 5 शिमाद अधिनियम का प्रार्थनापत्र स्वीकार कर अपीलाट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 शिमाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संशोधन होने एवं अपील का निस्तारण उपयुक्त की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

9. न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, अतः अपील अपीलाट खारिज किये जाने योग्य है।

अपीलाट का कब्जा हिस्से से ज्यादा पर हो तो क्या मुझे विभाजन में भूमि नहीं मिलेगी। अतः अधीनस्थ में संशोधन किया जा सकता है तथा यह संशोधन मौके पर कब्जा दिलाने के लिए किया गया था। को बौलें किया जा चुका है इस कारण इसे पुनः बौलें नहीं किया जा सकता है। 12 वर्ष बाद भी डिफ्री संशोधन किया जा सकता है। पूर्व में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी प्रारम्भिक डिफ्री दिनांक 13.03.2001

डिफेंस व सीनो अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठाधीन अधिकारी :- करतार सिंह पुनियाँ आर.ए.एस

अपील संख्या 2014/00381 (143/2014) 223 आर्टीएक्ट

1. गुरबचन सिंह पिसरन पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील

2. हरजीत सिंह } डिब्बी जिला हनुमानगढ़।

3. जगजीत सिंह

—अपीलापटस

बनाम

1. गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील डिब्बी जिला

हनुमानगढ़। (कौल)

1/1. गुड्डी उर्फ नसीबकौर पुत्री गुरनाम सिंह पत्नी सुखदेवसिंह जाति कम्हार सिख

बीपीओ दंढा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

2. सु० छोटी पुत्री पुत्री पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख निवासी मसानी तहसील डिब्बी

जिला हनुमानगढ़।

3. मोठा सिंह } पिसरन गुरनाम सिंह पुत्र पाखर सिंह जाति कुम्हार सिख

4. बलजीत सिंह } निवासी मसानी तहसील डिब्बी जिला हनुमानगढ़।

5. दलीप सिंह

6. राजस्थान सरकार जारि तहसीलदार डिब्बी जिला हनुमानगढ़।

— देखीपटस

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 21.03.2002 व डिफेंस दिनांक 22.03.2002 न्यायालय

सहायक कलेक्टर संगरिया कैम्प डिब्बी वाद संख्या 179/87 उनवानी गुरनाम सिंह

बनाम गुरबचनसिंह आदि एवं संशोधित निर्णय एवं डिफेंस दिनांक 28.05.2014

आज यह अपील रुबक हजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलत, श्री इन्द्रज

गादरा अधिवक्ता देखी 3, 4, 5, श्री रविन्द्र कुमार भाबिया राजकीय अधिवक्ता देखी 6 एवं

6 की ओर से पेश होकर हुआ है कि अपील अपीलत स्वीकार की जाती है एवं

अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 21.03.2002 एवं डिफेंस दिनांक 22.03.2002 एवं

संशोधित निर्णय एवं डिफेंस दिनांक 28.05.2014 खारिज किये जाते हैं। डिफेंस में हस्ताक्षर

व मुहर अदालत आज तारीख 9-9-21 को जारी की गई।

हनुमानगढ़  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
(करतार सिंह पुनियाँ आर.ए.एस)  
LAW

